जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 30 संख्याः 223 प्रभात उदयपुर, गुरुवार 15 जून, 2023 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

अमेरिका से आया रैड इयर्ड स्लाइडर टर्टल भारतीय जैव विविधता के लिए खतरा बन गया है। चूंकि यह बहुत छोटा है और इसका रख रखाव भी आसान है इसलिए पालतू जानवर के रुप में यह बेहद लोकप्रिय है। विशेषज्ञों का मत है कि, यह कछुआ स्थानीय कछुआ प्रजातियों के लिए खतरा बन गया है। असम के वाइल्डलाइफ बायॉलजिस्ट जयादित्य पुरकायस्थ, जो आई.यू.सी.एन. के टर्टल स्पेशलिस्ट ग्रुप के भी सदस्य हैं, ने कहा कि, रैड इयर्ड स्लाइडर टर्टल असल में साउथ ईस्टन यू.एस.ए. एवं मैक्सिको में मिलते हैं, पर वन्यजीवों के व्यापार के कारण अब ये भारत सहित समूचे विश्व में फैल गए हैं। भारत में स्थानीय कछुआ प्रजातियों को पालतू बनाना प्रतिबंधित है, पर, विदेशी प्रजातियों को पाला जा सकता है इसलिए कई लोग इन कछुओं को घर में रखते हैं। इस कछुए का उल्लेख कन्वैन्शन ऑन इन्टरनैशनल ट्रेड इन एन्डेजर्ड स्पीशीज़ में भी नहीं है। छोटे साइज़ के होने के कारण ये आराम से बाजार में मिल जाते हैं। घर पर भी रखे जाते हैं, लेकिन बड़ा होने पर जब ये छोटे तालाब में नहीं आते तो लोग इन्हें नदी या बड़े तालाब में छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा बन जाते हैं। स्थानीय प्रजातियों के विपरीत ये कछुए हर प्रकार की वनस्पति खा लेते हैं। डायरैक्टर ऑफ टर्टल सर्वाइवल अलायन्स, शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि, रैड इयर्ड स्लाइडर टर्टल बेहद आक्रामक होते हैं और स्थानीय प्रजातियों को खदेड़ देते हैं। इनके पंजे घातक होते हैं। ये भारत के कई राज्यों में फैल गए हैं तथा सॉफ्ट शैल व हार्डशैल सहित, अपनी तरह की हर प्रजाति के लिए खतरा बन गए हैं। शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि, चंडीगढ़ की सुखना लेक से लेकर गुवाहाटी के मंदिरों के तालाब, बैंगलौर की झीलों, मुम्बई में संजय गांधी नैशनल पार्क, दिल्ली की यमुना नदी, हर जगह ये कछुए मिलते हैं। इन्हें विश्व की 100 सबसे खराब घुसपैठिया प्रजातियों में एक माना जाता है। लगभग 73 देशों में इनकी आबादी पर नज़र रखी जाती है। पुरकायस्थ ने कहा कि, अगर इन कछुओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो, ब्रिटिश काल में दक्षिण अमेरिका से आए, जलकुंभी पौधे की तरह ये भी मुसीबत बन जाएंगे।

'वादे करके चुनाव जीतना तो आसान था, वादों की ''डिलीवरी'' उतनी ही मुश्किल है'

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले दिन से इस सच्चाई से वाकिफ हो रही है

- सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, बिजली की रेट में भारी वृद्धि से।
- पहले तो जनता राजी हो रही थी, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा से। पर अब घोषणा में, महीन अक्षरों में जो लिखा है, लोग उसके बारे में बारिकी से पूछ रहे हैं, राहत किस तरह से मिलेगी? क्या प्रक्रिया होगी, क्या मापदण्ड होंगे?
- एक तरफ फ्री बिजली, दूसरी ओर रेट बढ़ा देने से बिजली के बिल में 35 प्रतिशत की वृद्धि।
- एक आम आदमी के बिल में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि, इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन भी आंदोलन के मूड में आ गयी है।
- बिडाडी औद्योगिक क्षेत्र, जहां दुनिया की टॉप ब्राण्ड्स, टोयोटा, कोका कोला, ब्रिटेनिया के कारखाने हैं, की इकाइयाँ बिजली की दर की भारी वृद्धि के कारण महाराष्ट्र शिफ्ट होने की सोच रही हैं।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में चुनाव जीतना लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने से ज्यादा आसान था। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने चुनाव प्रचार में दी गई सभी 5 गारंटियों का क्रियान्वयन करना शुरु कर दिया, पर लोग अब इन गारंटियों के अंतिम प्रारुप के बारे में पूछ रहे हैं।

उदाहरण के लिए अब गाइडलाइन्स बन रही हैं कि मुफ्त सुविधाएं लेने के दायरे में कौन आता है तथा किन घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पर असंतोष के स्वर भी उभरने लगे हैं और लोग सरकार के काम काज को बारीकी से देख रहे हैं और इस समय की गई कोई भी गलती लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी पड़ सकती है।

भाजपा की हालात पर पूरी नज़र है और वह सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता, जब विपक्षी पार्टी वायदों पर अमल करने में सरकार की गलतियां गिनाने से बाज नहीं आती।

कांग्रेस को भारी तादाद में वोट देने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता बिजली की दरों में की गई वृद्धि है। सरकार की तरफ से किया गया यह स्पष्टीकरण कि, यह फैसला बोम्मई सरकार का था और वह इसे पलट नहीं सकती है, जनता को संतुष्ट नहीं कर रहा है।

बिजली बिल शुल्क बढ़ने पर सबसे बड़ी चिंता है औद्योगिक इकाइयों की धमकी कि वे कर्नाटक छोड़कर महाराष्ट्र चले जाएंगे।

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में गुस्सा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा व शिन्दे शिव सेना के बीच विज्ञापन युद्ध तीव्र हुआ

- पहले शिन्दे शिव सेना ने सभी अखबारों में विज्ञापन दिया, जिसका नारा थाः ''मोदी भारत में, शिन्दे महाराष्ट्र में, जनता की पसंद ड्रीम टीम''
- जवाब में भाजपा ने कैबिनेट की बैठक पर पोस्टर लगाये, पर मु.मंत्री की फोटो गायब थी पोस्टर में।
- दूसरे दिन, शिन्दे शिव सेना ने एक और फुल पेज का विज्ञापन छपवाया, जिसमें मोदी, शाह, आनंद डिगे व बाला साहब ठाकरे की फोटो सबसे ऊपर की पंक्ति में थी, बीच में एकनाथ शिन्दे का फोटो तथा नीचे की लाइन में शिन्दे शिव सेना के मंत्रियों की फोटो थी, पर, फड़नवीस का चित्र गायब था।
- संघर्ष इतना बढ़ा, इस विज्ञापन युद्ध से कि, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने वक्तव्य दिया कि, भाजपा विधानसभा चुनाव में 240 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और केवल 48 सीटें छोड़ेगी शिन्दे शिव सेना के लिये।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। समाचार पत्र-विज्ञापन-अभियान से महाराष्ट्र का राजनैतिक वातावरण गर्मा गया है। इस अभियान से ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टनरों- भाजपा और शिव सेना के एकनाथ शिंदे गुट के बीच सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है।

मंगलवार को प्रतिष्ठित अखबारों के मुखपृष्ठों पर पूरे पृष्ठ के विज्ञापन दिखाई दिये, जिनकी टैग लाइन थी- ''भारत के लिये मोदी, महाराष्ट्र के लिये शिंदे। सबकी प्रिय ''ड्रीम टीम''। उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस उस पोस्टर से न केवल गायब थे (जिस पर केवल प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फोटोग्राफ थे), बल्कि इस विज्ञापन में जी न्यूज़-मैट्रिज़ के एक सर्वे के हवाले से यह भी कहा गया था कि अगले चुनावों में 26.1 प्रतिशत लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे को देखने की इच्छा व्यक्त की है, जबकि 23.2 प्रतिशत लोगों की पसंद फड़नवीस रहे हैं।

भाजपा ने अविवेकपूर्ण संकेत देते हुये संकेत दिये हैं कि पार्टी इस पोस्टर से व्याकुल है। भगवा पार्टी ने उसी दिन हुई उस कैबिनेट मीटिंग के पोस्टर लगा दिये, जिनमें मुख्यमंत्री शिंदे का फोटो नदारद था।

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को एक और विज्ञापन दिया, जिसमें बैनर पर सबसे ऊपर मोदी, अमित शाह, आनन्द दिप्पे तथा बाला साहेब ठाकरे सहित कई नेताओं के फोटोग्राफ थे, शिंदे का फोटो बीचों बीच था, तथा बैनर के नीचे वाले हिस्से पर (शिंदे के अलावा) शिव सेना के सभी 9 मंत्रियों के फोटो दिये गये थे।

अगले साल होने वाले लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों से पहले, जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिंदे स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना चाह रहे हैं, जबकि भाजपा की कोशिश उनकी पार्टी को क्षति पहुँचाने की है। चन्द महीने पहले, राज्य भाजपा के अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुल ने यह कहते हुये खलबली पैदा कर दी थी कि वे फड़नवीस को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। मार्च में बावनकुले ने कहा था कि भाजपा राज्य की 240 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तथा केवल 48 सीटें ही शिंदे की पार्टी के लिये छोड़ेंगी। पिछले महीने, भाजपा विधायक संजय केलकर ने कल्याण सीट पर अपना दावा ठोका था, जिसका प्रतिनिधित्व इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है!
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

न्यू इंडिया अश्यौरैंस कंपनी पर 1.30 लाख रू. का जुर्माना

जयपुर, 14 जून (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय, ने वाहन का बीमा क्लेम नहीं देने पर, द न्यू इंडिया अश्यौरैंस कंपनी पर एक लाख तीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही आयोग ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ठीक करने के लिए परिवादी की ओर से खर्च की गई करीब 15 लाख बीस हजार रुपए की राशि, नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने ये आदेश रामनिवास यादव के परिवाद पर दिए।

- जिला उपभोक्ता आयोग ने क्लेम राशि नहीं देने के कारण बीमा कम्पनी पर जुर्माना लगाया और परिवादी की ओर से खर्च 15 लाख रू. की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।

आयोग ने अपने आदेश में कहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नये संसद भवन में प्रदर्शित भित्ति चित्र ने बवाल मचाया

इस भित्ति चित्र में सम्राट अशोक के समय के भारत का चित्रण है, जिसमें दिखाया गया है कि, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान का काफी हिस्सा व सैन्ट्रल एशिया का काफी इलाका सम्राट अशोक का साम्राज्य था

- स्वाभाविक ही है, पड़ोसी देशों ने इस नक्शे पर काफी आपत्ति जतायी है। क्योंकि, उनके अनुसार यह भारत की विस्तारवादी महत्वकांक्षा का सबूत है।
- वे रूस का उदाहरण देते हैं कि, पीटर द ग्रेट के नक्शे को पुतिन ने उपयोग में लिया था और यूक्रेन को रूस का हिस्सा बताया था।
- इसी प्रकार चीन भी, चीन के साम्राज्य को आधार बनाकर साऊथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार बताता है। जैसा कि विदित ही है, साऊथ चाइना सी वर्तमान में विश्व में व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण ''सी-रूट'' (समुद्री मार्ग) है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। नए संसद भवन में लगे नक्शे ने पड़ोसी देशों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को न केवल चिंतित कर दिया है और विवाद को भी जन्म दिया है।

कई जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस नक्शे को समकालीन भारत में इतिहास की संशोधनवादी व्याख्या का एक उदाहरण बता रहे हैं जिससे विवाद व कूटनीतिक संकट पैदा हो रहा है।

भारत के कुटनीतिक विभाग ने हालांतिक इन चिंताआं व आलोचनाओं को यह कहकर नकार दिया कि यह नक्शा अशोक साम्राज्य को दर्शाता है। यह भारत की साम्राज्य निर्माण महत्वाकांक्षा का परिचायक नहीं है।

यह नक्शा नए संसद भवन की दीवार पर बना एक भित्ती चित्र है जिसमें तीसरी सदी ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के साम्राज्य को दर्शाया गया है। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य बहुत दूर तक फैल गया था जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीलोन (श्रीलंका), अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ भाग शामिल थे।

कुछ मुखर राष्ट्रवादी बताते हैं कि 1947 का खंडित भारत असली भारत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सरकारी डॉक्टर घर में दवाएं रख सकते हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए, ड्रग्स एण्ड कॉस्मैटिक्स एक्ट 1940 के तहत गिरफ्तार डॉक्टर को दोषमुक्त करते हुए निर्णय दिया कि, एक सरकारी डॉक्टर अपने घर पर दवाएं रख सकता है तथा मरीजों को दे सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देकर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और घर में दवा रखने के आरोप में गिरफ्तार डॉ. अतिलक्ष्मी को दोष मुक्त कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, डॉक्टर त्वचा विभाग का हैड ऑफ द डिपार्टमैंट व मैडिकल कॉलेज में अस्टिैंट प्रोफेसर है तथा ड्रग इन्स्पैक्टर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

करोड़पतियों का भारत से पलायन बदस्तूर जारी है

देश छोड़ कर जाने वाले धनाढ्यों के लिये सबसे पसंदीदा देश है दुबई व सिंगापुर

- भारतीयों की दुबई में बढ़ती संख्या के कारण, दुबई को भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है।
- यह भी सच है कि, इस पलायन से भारत ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि 7 वर्ष में भारत में इतने नये धनाढ्य पनप रहे हैं कि, जाने वालों की संख्या का खास असर नहीं पड़ता।
- पर, अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि, पलायन करने में सबसे आगे रहते हैं करोड़पति धनाढ्य। अगर देश का औद्योगिक या व्यापारिक माहौल थोड़ा भी गड़बड़ाता है तो, धनाढ्य सबसे पहले भागते हैं, अतः देश में धनाढ्यों का पलायन, इस बात का प्रारंभिक संकेत जरूर माना जा सकता है कि, कुछ ठीक नहीं चल रहा देश की इकॉनमी में।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। हेनली प्राइवेट वैल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, देश से अरबपतियों का पलायन जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि 6500 हाई-नैट वर्थ इन्डीविजुअल्स (एच.एन.डब्ल्यू.आई.) के 2023 में निवेश में जाकर बस जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि एच.एन.डब्ल्यू.आई. वैश्विक स्तर पर धन एवं निवेश के देश से बाहर जाने की प्रवृत्ति पर नजर रखती है।

लंदन स्थित हेनली एण्ड पार्टनर्स प्रतिवर्ष ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि, ''धनवान भारतीय परिवारों के पसंदीदा देश दुबई तथा सिंगापुर बने हुये हैं। दुबई, जो ''भारत के पांचवे महानगर'' के रूप में प्रसिद्ध है, खासतौर से सरकार संचालित ग्लोबल इन्वैस्टर ''ग्लोबल वीज़ा'' प्रोग्रैस, अनुकूल टैक्स व्यवस्था, विशाल बिजनैस ईकोसिस्टम तथा सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण माहौल के कारण आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में, पुर्तगाल भी भारतीय अरबपतियों की बड़ी धनराशि का गंतव्य बन गया है क्योंकि लिस्बन में अपने ''गोल्डन रेजीडेंस परमिट प्रोग्रैस'' की घोषणा कर दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुर्तगाल का आकर्षक ''परमिट प्रोग्रैस'' अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुंच गया है पुर्तगाल क्योंकि पुर्तगाल गोल्डन रेजीडेन्स परमिट प्रोग्रैस की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, जिसके चलते पुर्तगाल के रियल एस्टेट तथा अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में उल्लेखनीय निवेश हुआ था।

इस साल देश से बाहर जाकर बसने वाले अरबपतियों के मामले में चीन पहले नम्बर पर रहा है। अनुमानतः चीन के 13,500 एन.एन. डब्ल्यू.आई. विदेशों में जाकर बस गये हैं। इस संदर्भ में, चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत रहा है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी सबसे बड़ी संख्या में अरबपतियों के विदेशों में बस जाने के बावजूद, भारत की स्थिति में सुधार की संभावना है क्योंकि गत वर्ष, विदेश में बस जाने वाले भारतीयों की संख्या 7500 थी। रिसर्च ऐट न्यू वर्ल्ड वैल्थ'' के प्रमुख एन्ड्रू अमोइल्स कहते हैं कि अरबपतियों का ''यह निर्गमन कोई खास चिंता का विषय नहीं है क्योंकि भारत से जितने अरबपति विदेश जाकर बस रहे हैं, उससे काफी ज्यादा अरबपति यहां बन रहे हैं।''

''हेनली एण्ड पार्टनर्स'' के सी.ई.ओ. ज्यूर्ग स्टीफन कहते हैं कि विदेश जाने वाले अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी प्रायः किसी देश में विश्वास की कमी की ओर संकेत करती है क्योंकि सबसे पहले आम तौर से एच.एन.आई. ही देश छोड़कर जाते हैं। वे कहते हैं, ''सम्पन्न लोग बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं तथा उनके देश छोड़कर जाने से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी आगामी संभावना की पूर्व चेतावनी के संकेत मिल जाते हैं।''

इसके अलावा, धन के विदेश जाने की प्रवृत्ति महामारी के पहले वाली स्थितियों की ओर लौट रही है तथा ऑस्ट्रेलिया धन के गंतव्य स्थानों में पुनः पहले नम्बर पर आता प्रतीत हो रहा है तथा चीन, देश छोड़कर जाने वाले एच.एन.आई. की सर्वोच्च संख्या का साक्षी बना हुआ है। रिपोर्ट में सामने आया है कि इस वर्ष देश छोड़कर जाने वाले धनी परिवार ऑस्ट्रेलिया, यू.ए.ई., सिंगापुर, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड को अपने पसंदीदा देश मान रहे हैं, जबकि जिन देशों से सबसे अधिक, अमीर परिवार विदेशों में जा रहे हैं, उनमें चीन, भारत, इंग्लैण्ड, रूस तथा ब्राजील अग्रणी हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल ज्यादातर एच.एन.आई. को आकर्षित करने वाले 10 शीर्ष देशों में से 9 देशों ने ''इन्वैस्टमैंट माइग्रेशन प्रोग्रैस'', जिसे ''गोल्डन वीजा प्रोग्रैस'' के नाम से भी जाना जाता है, प्रस्तावित किया है। यह प्रोग्रैस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अपनी ओर खींचने में चुम्बक का काम कर रहा है। रिपोर्ट कहती है, ''सिंगापुर,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पंजाब में अभी भी 1934 वाले सिविल सेवा नियम चल रहे हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जून। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सिविल सर्विस रूल्स, 1934 को अपडेट या संशोधित न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि ऐसा होने से पदों का सही एवं अधिकृत विवरण दूर हो सकेगा तथा भ्रम की स्थिति का निराकरण हो सकेगा।

- कोर्ट ने यह कहते हुए पंजाब सरकार को फटकारा और सिविल सेवा नियमों को अपडेट करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन बैंच ने कहा कि नियम समय के साथ नहीं चले है तथा लम्बा समय गुजर जाने के कारण विसंगतियाँ